भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं 1323**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन के साथ व्यापार संबंध

1323 **श्री दिग्विजय सिंहः**

श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच मूल्य के संदर्भ में आयात और निर्यात का उत्पाद - वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान चीन और भारत के बीच हुए व्यापार के संदर्भ में भारत में चीन से किए जाने वाले आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान चीन के साथ व्यापार में भारत को वर्ष वार कुल कितना व्यापार घाटा हुआ है; और

(घ) क्या सरकार चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने की योजना बना रही है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): मूल्य के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच आयात और निर्यात का उत्पाद वार विवरण वाणिज्य विभाग की वेबसाइट https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp पर देखा जा सकता है।

(ख) और (ग): पिछले पांच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 के दौरान चीन से भारत के आयात ने मिली-जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। हांलाकि पहले दो वर्षों (2019-20 और 2020-21) के दौरान आयात में कमी आई, तथापि अगले तीन वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का विवरण डीओसी की वेबसाइट https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp. पर देखा जा सकता है । चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2004-05 से 2013-14 के दौरान 42.85 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है, जबकि 2014-15 से 2023-24 के दौरान यह घटकर 6.45 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर आ गया है, जो यह स्पष्ट रूप से

दर्शाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान चीन से अत्यधिक आयात वृद्धि को नियंत्रित करने में सरकार को सफलता मिली है।

(घ) सरकार समय-समय पर चीन के साथ व्यापार संतुलन को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाती रही है। चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चा माल है और इनका उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है।

सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, व्हाइट गुड्स और दूरसंचार उपकरण जैसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं, जहां आयात पर पर्याप्त निर्भरता है। सरकार ने अवमानक आयातों को रोकने के लिए सख्त गुणवत्ता मानक, परीक्षण प्रोटोकॉल और अनिवार्य प्रमाणन की भी शुरूवात की हैं। सरकार भारतीय व्यवसायों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। घरेलू उद्योग को सहयोग देने के लिए सरकार ने आयात पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना दिया है।

सरकार नियमित रूप से आयात में वृद्धि को मॉनिटर करती है और उचित कार्रवाई करती है। अवमानक आयात को रोकने के लिए विभिन्न उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय को अनुचित व्यापार प्रक्रियोओं के विरूद्ध व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है।

***